

[2023] 1 एस. सी. आर 865 ए

ए.

पीआर। आय कर आयोग (छूट) दिल्ली

बनाम

लोक समाजक सेवक (सिविल अपील सं. (एस))।614 2023 का) 31 जनवरी, 2023

बी.

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961:एसएस।2(15) और 11 (1)-चैरिटेबल ट्रस्ट-छूट का लाभ-तथ्यों के आधार पर, राष्ट्र निर्माण, सामान्य जागरूकता और लोगों के कल्याण के लिए 1921 में स्थापित परंतुक ी-पंजीकृत सोसायटी-एक प्रिंटिंग प्रेस और एक समाचार पत्र का प्रबंधन और संचालन करने वाली परंतुक ी सोसायटी-छूट के लाभ का दावा-निर्धारण अधिकारी द्वारा एस.2(15) इस आधार पर कि निर्धारिती व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में शामिल है-हालाँकि, अपीलीय आयुक्त ने निर्धारिती की याचिका को स्वीकार कर लिया-न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:अपीलीय आयुक्त, आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय ने केवल भारत व्यापार संवर्धन संगठन मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया-हालाँकि, एस की व्याख्या के संबंध में कानून।2 (15) बदलाव आया है, क्योंकि

सी.

डी.

ई.

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण मामले में निर्णय-मामला

पुनः जाँच की जानी चाहिए और यह प्रश्न कि क्या निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि छूट के लिए योग्य है।2 (15) या एस।11 नए सिरे से जाना-दस्तावेजों और प्रासंगिक कागजातों की जांच करने और इस मुद्दे पर नए निष्कर्ष देने के लिए मूल्यांकन अधिकारी।

एफ.

भारत व्यापार संवर्धन संगठन बनाम आयकर महानिदेशक (छूट) 371 आईटीआर (डेल) 333

-

संदर्भित किया गया।

जी.

सी. आई. टी. बनाम अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण **2022**

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **1461**-पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील No.614

2023.

एच.

865

866

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

2021 के आई. टी. ए. No.161 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.11.2021 निर्णय और आदेश से।

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., जे. के. मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जोगी स्कारिया, प्रदीप कुमार गुप्ता, सुश्री बीना विक्टर, सुश्री प्रिया एम., रवि लामोद, राज बहादुर यादव, अशोक पाणिग्रही, चिनमयी चंद्र, प्रशांत सिंह, श्रीमती मोनिका बेंजामिन, सुश्री मीना देवी, प्रसेनजीत सरकार, डी. महेश बाबू, गणेशन सुब्बियन, शिशिर पिनाकी, धनेश्वर गुडापल्ली, कसोजू महेश चारी, सुश्री मल्लिका दास, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

सी.

एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०

1. विशेष अवकाश दिया गया। श्री डी. महेश बाबू एकमात्र प्रत्यर्थी (जिसे इसके बाद "निर्धारिती" कहा जाता है) की ओर से अपील का नोटिस माफ कर देते हैं। अपील पर आखिरकार सुनवाई होती है।

डी.

2. आयकर आयुक्त (इसके बाद "राजस्व" के रूप में संदर्भित) दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित हैं। विवादित फैसले ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ("आई. टी. ए. टी.") के फैसले को बरकरार रखा, जिसने आयकर आयुक्त (अपील) (जिसे इसके बाद "अपीलीय आयुक्त" कहा जाता है) द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की पुष्टि की। अपीलीय आयुक्त

और आई. टी. ए. टी. की राय थी कि प्रत्यर्थी संगठन (एक पंजीकृत सोसायटी, जिसे इसके बाद "निर्धारिती" भी कहा जाता है) छूट के लाभ का हकदार एक धर्मार्थ न्यास था और यह कि यह आयकर अधिनियम की धारा 12 एए और 80 जी (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाता है) के तहत पंजीकृत है, वैध था।

ई.

एफ.

3. तथ्य यह है कि निर्धारिती सोसायटी की स्थापना वर्ष 1921 में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय द्वारा राष्ट्र निर्माण, सामान्य जागरूकता और लोगों के कल्याण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी। 1928 में ओडिशा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री पं. गोपा बंधु दास ने लोगों के कल्याण के लिए अपनी संपत्ति और अपने प्रिंटिंग प्रेस की एक वसीयत बनाई जो उड़िया समाचार पत्र "समाज" का प्रबंधन कर रहा है।

जी.

1 आई. टी. ए. सं. 161/2021 ए. में दिनांकित 16.11.2021

एच.

867

पीआर। आय कर आयोग (छूट) दिल्ली बनाम लोक समाज के सेवक [एस. रवींद्र भट, जे.]

निर्धारिती अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का आनंद ले रहा था, लेकिन ए. वाई. 1973-74 के दौरान इसे अस्वीकार कर दिया गया था और बाद में आई. टी. ए. टी. द्वारा इसकी अनुमति दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई। निर्धारिती को पहले भी अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (iv) के तहत तीन साल यानी 1990-91 से 1992-93 के लिए छूट दी गई थी। निर्धारिती ने लाजपत नगर और नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बलवंत राय मेहता विद्या भवन और लाजपत नगर में एक चिकित्सा केंद्र और दिल्ली के द्वारका में वृद्धाश्रम के नाम पर विद्यालय स्थापित किए हैं और चला रहे हैं। निर्धारिती ओडिशा में गोपा बंधु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के नाम पर एक अस्पताल भी बना रहा है। निर्धारिती को धारा 11 (1) के तहत भी छूट दी गई थी, लेकिन ए. वाई. 2010-11 और 2011-12 के दौरान इसे अस्वीकार कर दिया गया है। निर्धारिती अधिकारी ने धारा 2 (15) के परंतुक को लागू करते हुए इस आधार पर छूट देने से इनकार कर दिया कि निर्धारिती व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में शामिल है क्योंकि वह एक मुद्रण प्रेस और एक समाचार पत्र का प्रबंधन और संचालन करता है। निर्धारिती ने तर्क दिया कि यह मुख्य रूप से धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल एक गैर-लाभकारी संस्थान था और किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं था।

बी.

सी.

डी.

4. निर्धारिती ने अपीलीय आयुक्त से संपर्क किया जिन्होंने उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि उसके द्वारा अर्जित आय को छूट का लाभ मिलना चाहिए। राजस्व ने आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय में अपील में मामले को आगे बढ़ाया, दोनों असफल रहे। नतीजतन, इसने विशेष अनुमति द्वारा अपील में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

ई.

5. राजस्व की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि अपीलीय आयुक्त और न्यायाधिकरण ने निर्धारिती को छूट देने में गलती की। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह इंगित करते हैं कि आई. टी. ए. टी. ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन किया।

एफ.

भारत व्यापार संवर्धन संगठन बनाम के महानिदेशक में न्यायालय

आय कर (छूट) 2 और अन्य निर्णय। यह आग्रह किया गया था कि इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए वे निर्णय अब अच्छे कानून नहीं हैं।

जी.

सी. आई. टी. बनाम अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण 3, जिसके द्वारा न्यायालय उन गतिविधियों को आयोजित किया है जो व्यापार की प्रकृति में हैं, और द्वारा जारी है

2 371 आई. टी. आर. (डेल) 333

3 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1461 ए

एच.

868 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के लिए स्थापित न्यास को कुछ मानदंड निर्दिष्ट करने होते हैं।

6. विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस मामले में निर्धारिती न केवल समाचार पत्र की बिक्री से राजस्व अर्जित कर रहा है, बल्कि पर्याप्त विज्ञापन राजस्व भी अर्जित कर रहा है।

बी.

7. निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता का आग्रह है कि इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि अपीलीय आयुक्त के साथ-साथ आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय ने छूट के लिए अपने दावे को इस आधार पर बरकरार रखा है कि यह एक धर्मार्थ न्यास है जिसे छूट के लिए पात्र माना जाता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि विज्ञापन के माध्यम से आय उत्पन्न करने की गतिविधि केवल आकस्मिक है और विज्ञापन से आय को न्यास के मुख्य उद्देश्य का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसे अपने धर्मार्थ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

सी.

डी.

विश्लेषण और निष्कर्ष

8. संबंधित निर्धारण वर्ष के दौरान, निर्धारिती समिति ने समाचार पत्रों से आय के संबंध में छूट का दावा किया, जिसमें विज्ञापन राजस्व शामिल था, दिल्ली में अपनी गतिविधियों से '9,52,57,869/- और' 2,16,50,901 के अधिशेष तक।

ई.

9. अहमदाबाद शहरी विकास मामले में इस न्यायालय का फैसला

प्राधिकरण ने यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जांच की थी कि क्या वे धर्मार्थ प्रकृति के हैं, जो सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्यों के साथ न्यासों या समितियों से संबंधित हैं। न्यायालय ने तब धारा 2 (15) के तहत "धर्मार्थ उद्देश्यों" की सही व्याख्या के संबंध में अपने निष्कर्षों को दर्ज किया और निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया:

एफ.

“IV. निष्कर्षों का सारांश

267. पूर्वगामी चर्चा और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, "धर्मार्थ उद्देश्य" की बदली हुई परिभाषा की व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। (01.04.2009), साथ ही बाद के संशोधन, और आईटी अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधान।

जी.

एच.

869

पीआर। आय कर आयोग (छूट) दिल्ली बनाम लोक समाज के सेवक [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

ए.

ए. धारा 2 (15) के तहत सामान्य परीक्षण

ए. 1. यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने वाला निर्धारिती किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय में खुद को संलग्न नहीं कर सकता है, या किसी भी विचार ("उपकर, या शुल्क, या कोई अन्य विचार") के लिए उसके संबंध में सेवा प्रदान नहीं कर सकता है।

बी.

ए. 2। हालांकि, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में, संबंधित न्यास, समाज या ऐसा कोई अन्य संगठन, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय कर सकता है या विचार के लिए उसके संबंध में सेवाएं प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि (i) व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की गतिविधियाँ जी. पी. यू. के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ी हों ("वास्तविक निष्पादन". डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2016 अंतःस्थापित)। और (ii) उसके संबंध में ऐसी व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधि या सेवा से प्राप्त रसीद, वर्षों में संशोधित मात्रात्मक सीमा से अधिक नहीं है। 10 लाख डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2009; फिर रु. 25 लाख डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2012; और अब पिछले वर्ष की कुल प्राप्तियों का 20 प्रतिशत, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2016);

सी.

डी.

ए. 3. आम तौर पर, ऐसी गतिविधि (सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने) के लिए विचार के लिए किसी भी राशि का प्रभार, जो लागत के आधार पर या नाममात्र लागत से अधिक है, को "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" या उसके संबंध में कोई सेवा नहीं माना जा सकता है। यह केवल तभी होता है जब शुल्क विचाराधीन निर्धारिती द्वारा की गई लागत से स्पष्ट रूप से या महत्वपूर्ण रूप से अधिक होते हैं, कि वे "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय" के प्रति "उपकर, या शुल्क, या किसी अन्य विचार" की शरारत के दायरे में आते हैं। इस संबंध में, न्यायालय ने दृष्टान्तों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि लागत या नाममात्र के आधार पर प्रदान की जाने वाली किस तरह की सेवाओं या वस्तुओं को आम तौर पर निर्णय के मुख्य भाग में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की शरारत से बाहर रखा जाएगा।

ई.

एफ.

जी.

ए. 4. धारा 11 (4 ए) की व्याख्या धारा 2 (15) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए, जिसके साथ कोई टकराव नहीं है। चला रहे हैं।

एच.

ऐसी गतिविधियों के संबंध में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या सेवा की प्रकृति की गतिविधि जी. पी. यू. उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में आयोजित की जानी चाहिए और इसलिए आय, लाभ या अधिशेष या लाभ आकस्मिक होना चाहिए। धारा 11 (4 ए) में अलग-अलग लेखा पुस्तिकाओं को बनाए रखने की आवश्यकता भी यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता के अनुरूप है कि धारा 2 (15) के परंतुक में परंतुक मात्रात्मक सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसी तरह, धारा 13 (8) का सम्मिलन, धारा 10 (23 सी) का सत्रहवाँ परंतुक और धारा 143 (3) का तीसरा परंतुक (सभी w.r.e.f। 01.04.2009), इस व्याख्या की पुष्टि करते हैं और वैधानिक परंतुक ों में एकरूपता लाते हैं।

बी.

सी.

10. इस न्यायालय ने एक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त आय की प्रकृति पर भी विचार किया था, जो एक समाचार पत्र का प्रबंधन कर रहा था। उस निर्धारिती, अर्थात् ट्रिब्यून ट्रस्ट से संबंधित टिप्पणियां प्रासंगिक हैं:

डी.

“257. विवादित फैसले से यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ट्रस्ट की गतिविधियों को 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' के उद्देश्यों के वित्तपोषण का गठन करने के लिए प्रिवी काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था; इसके अलावा केवल इसलिए कि हजारों समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। यह अभी भी एक जी. पी. यू. दान जारी है।

ई.

258. तब सवाल यह है कि क्या न्यास द्वारा प्राप्त प्राप्तियों और आय की प्रकृति, वास्तव में समाचार पत्र प्रकाशन की अपनी गतिविधि को पूरा करने के दौरान, किसी भी विचार के लिए "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में" या "व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में सेवा" के रूप में वर्णित की जा सकती है। प्रस्तुतियों के दौरान, यह आग्रह किया गया था कि विज्ञापन राजस्व को व्यावसायिक या वाणिज्यिक प्राप्तियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह वस्तुतः जीवन-रक्त है जो समाचार पत्रों के प्रकाशन की गतिविधि को बनाए रखता है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि समाचार पत्र के प्रकाशन और वितरण की गतिविधि को बनाए रखने का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति है, ए

एफ.

जी.

एच.

871

पीआर। आय कर आयोग (छूट) दिल्ली बनाम लोक समाज के सेवक [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

क्योंकि इसका प्रभाव आम जनता को वर्तमान मामलों और घटनाक्रमों के बारे में सूचित करने और शिक्षित करने दोनों का होता है। विज्ञापनों का समावेश आम जनता के लिए सूचना के रूप में भी काम करता है, विशेष रूप से रोजगार, संसाधनों की उपलब्धता आदि के क्षेत्रों में। इसलिए, विज्ञापन का प्रकाशन आंतरिक रूप से समाचार पत्रों के मुद्रण और प्रकाशन की गतिविधि से जुड़ा हुआ है।

बी.

259. न्यायालय की राय में समाचार पत्र द्वारा विचार के लिए विज्ञापनों के प्रकाशन को शुल्क या विचार के लिए व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने की प्रकृति की गतिविधि के रूप में नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में ट्रस्ट ("द ट्रिब्यून") द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र को मुख्य रूप से विज्ञापन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि ट्रस्ट द्वारा इस तरह के विज्ञापनों को प्रकाशित करना व्यवसाय नहीं है। न्यास का उद्देश्य समाचार पत्रों के प्रकाशन में शामिल होना या संलग्न होना है। विज्ञापनों का प्रकाशन स्पष्ट रूप से उन प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए होता है जो लाभ की प्रकृति में होती हैं। अब, धारा 2 (15) की संशोधित परिभाषा के आधार पर, जी. पी. यू. दान स्वयं को व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधि या लाभ में संलग्न कर सकते हैं, केवल तभी जब ऐसी गतिविधियों से प्राप्त प्राप्ति किसी दिए गए वर्ष में अर्जित कुल प्राप्ति की मात्रात्मक सीमा से अधिक न हों। यद्यपि परंतुक ी का यह तर्क कि विज्ञापन का प्रकाशन आंतरिक रूप से समाचार पत्र गतिविधि से जुड़ा हुआ है (जिससे धारा 2 (15) के परंतुक के उपखंड (i) को पूरा किया जाता है, अर्थात् उद्देश्य की प्रगति की दिशा में गतिविधि को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने के क्रम में एक गतिविधि) स्वीकार्य है, फिर भी, धारा 2 (15) के परंतुक के उपखंड (ii) द्वारा लगाई गई शर्त को भी पूरा करना होगा। वर्तमान मामले में, उस प्रतिशत को पार कर लिया गया था, जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

11. वर्तमान मामले में अपीलीय आयुक्त, आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय ने केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन में न्यायालय।लेकिन कानून के साथ

एच.

872

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

धारा 2 (15) की व्याख्या के संबंध में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (ऊपर) में निर्णय के लिए।

नतीजतन, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान मामले में निर्धारिती के हाथों में प्राप्तियों की प्रकृति पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला भेजा जाना चाहिए।नतीजतन, मामले की फिर से जांच करने की आवश्यकता है, और इस सवाल पर कि क्या निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि धारा 2 (15) या धारा 11 के तहत छूट के लिए योग्य है, नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

बी.

12. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, राजस्व की अपील आंशिक रूप से सफल होती है। एओ दस्तावेजों और प्रासंगिक कागजातों की जांच करेगा और इस मुद्दे पर नए निष्कर्ष देगा कि क्या प्रत्यर्थी एक धर्मार्थ न्यास है, जो अपनी आय से छूट का हकदार है।एओ सुनवाई पूरी करेगा और चार महीने के भीतर आदेश पारित करेगा।अपील को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।

सी.

डी.

निधि जैन

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायक: शाश्वत जैन, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.